तापमान

भोपाल	23.0°	30.0°
इंदौर	21.0°	30.0°
जबलपुर	23.0°	33.0°
ग्वालियर	27.0°	34.0°
सागर	23.0°	32.0°

नईदुनिया

वर्ष- 80
(भोपालः वर्ष 41 अंक 282, पृष्ठ 12)
भाद्रपक्ष, कृष्ण चतुर्दशी संवत् 2083
गुरुवार, 10 सितम्बर 2026
कीमतः 3:00 रुपये

www.naidunialive.com
भोपाल संस्करण
भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

राजधानी... दुबई दौरे में मध्यप्रदेश को मिले 53 हजार ...

खेल... भारतीय टीम से मुकाबले के लिए तैयार हैं: सैंटनर

व्यापार... सहारा रिफंड पोर्टल फिर सक्रिय, लाखों निवेशकों ...

देश-विदेश... बांग्लादेश की धमकी कहा- हसीना को भारत...

मध्यप्रदेश सरकार ने इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड 50% बढ़ाया, आंदोलन खत्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश सरकार ने इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड 50 प्रतिशत बढ़ाकर 21,500 रुपये करने का फैसला किया है। इसके बाद तीन दिन से चल रहा आंदोलन खत्म हो गया और इंटर्न डॉक्टर काम पर लौट गए। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि इंटर्न, जूनियर डॉक्टर और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद मांगें स्वीकार की गईं। प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के मामले में दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है। मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है।

5 राज्यों के चुनाव में भाजपा को 1,472.8 करोड़ चंदा, कांग्रेस से सात गुना अधिक

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः *इसी वर्ष अप्रैल में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को उसके केंद्रीय मुख्यालय में करीब 1,472.8 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। निर्वाचन आयोग के अनुसार यह राशि कांग्रेस की केंद्रीय और राज्य इकाइयों की 207.17 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति से सात गुना से अधिक है। इन चुनावों में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल थे। चार मई को घोषित परिणामों में असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत हुई थी। केरल में इंडिया गठबंधन और तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कझगम तथा कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। चुनावी अवधि में भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय का शेष धन भी बढ़ा। 15 मार्च को यह 6,722.6 करोड़ रुपये था, जो छह मई को बढ़कर 7,627.2 करोड़ रुपये हो गया। इस तरह इसमें 904.6 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस के केंद्रीय मुख्यालय और पांच राज्य इकाइयों के पास चुनावी अवधि की शुरुआत में करीब 169.06 करोड़ रुपये थे। छह मई तक यह राशि घटकर करीब 103.2 करोड़ रुपये रह गई। इस तरह कांग्रेस के चुनावी कोष में 65.86 करोड़ रुपये की कमी आई। भाजपा ने असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में करीब 159.7 करोड़ रुपये खर्च किए। इनमें 130.4 करोड़ रुपये सामान्य पार्टी प्रचार पर खर्च हुए। असम में सबसे ज्यादा 96.27 करोड़ रुपये खर्च किए गए। तमिलनाडु में 51.56 करोड़ और पुडुचेरी में 11.90 करोड़ रुपये खर्च हुए। कांग्रेस ने पांचों राज्यों में सामान्य पार्टी प्रचार पर 143 करोड़ रुपये और उम्मीदवारों पर 105.55 करोड़ रुपये खर्च किए। उसका कुल चुनावी खर्च 248.55 करोड़ रुपये रहा। कांग्रेस के सामान्य प्रचार खर्च में केरल का हिस्सा सबसे अधिक 59.28 करोड़ रुपये रहा।*

गरबा देखने आने में गलत नहीं: अमृता

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबईः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा कि मुस्लिम भी गरबा देखने आते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। त्योहार सभी को साथ लेकर चलने वाले होने चाहिए। अमृता मंगलवार को चंद्रपुर के महाशिवलिंग मंदिर में आयोजित रुद्राभिषेक कार्यक्रम में पहुंची थीं। मंत्री नितेश राणे के नवरात्रि गरबा आयोजनों में मुस्लिमों की एंट्री के विरोध वाले बयान पर उन्होंने यह बात कही। गणेशोत्सव में तेज संगीत और डीजे के विवाद पर उन्होंने कहा कि त्योहार मनाते समय सरकार और अदालतों के नियमों का पालन होना चाहिए। सार्वजनिक आयोजनों से अन्य नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

खास-खबरें

राहुल वीवीआईपी नहीं कोर्ट में याचिका

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः राहुल गांधी के सेना पर दिए बयान से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई। शिकायतकर्ता के वकील गौरव भाटिया ने कहा कि मामला करीब पांच महीने से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोई वीवीआईपी नहीं हैं कि मामले की सूची में इतना समय लगे। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत के सामने सभी बराबर हैं। उन्होंने जल्द सुनवाई के लिए आवेदन दाखिल करने को कहा। मामला वर्ष 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा है। यात्रा सात सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक चली थी।

लाल किला विस्फोट जांच में उमर मास्टरमाइंड

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की जांच में उमर उन नबी को आतंकी साजिश का मास्टरमाइंड बताया गया है। जांच एजेंसी की नौ सितंबर को सामने आई आरोप पत्र के अनुसार, नबी हमले में इस्तेमाल वाहन में मौजूद था और विस्फोट में उसकी मौत हो गई थी। जांच के मुताबिक, नबी उर्फ पिंडा और राहुल भट वर्ष 2022 की शुरुआत से निष्क्रिय हो चुके अंसार गजवत-उल-हिंद मॉड्यूल को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहे थे। इस मॉड्यूल को जांच में अल-कायदा से जुड़े नए रूप के तौर पर बताया गया है। विस्फोट में 11 लोगों की मौत और 29 लोग घायल हुए थे।

उमर ने पूरा वंदे मातरम गाया, कांग्रेस को जलन

नईदुनिया ब्यूरो, श्रीनगरः मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की मौजूदगी में वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से पार्टी के साथ खड़े रहने की अपील की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि गठबंधन सहयोगी होने के नाते कांग्रेस यह तय नहीं कर सकती कि वंदे मातरम कितना गाया जाए। पार्टी नेता बशीर अहमद ने कहा कि यह लोगों की पसंद का मामला है। कांग्रेस कार्यसमिति ने अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के छह में से शुरुआती दो पद गाने का फैसला किया था। भाजपा ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग की राजनीति करने वाली पार्टी बताया।

डॉ. यादव ने अस्पताल पहुँचकर पीड़ितों का हालचाल पूछा

न्यायिक जाँच कराई जाएगी: सीएम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल/सागरः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सागर जिले के बंडा-शाहगढ़ क्षेत्र में अवैध शराब से लोगों की हुई मृत्यु के प्रकरण में कठोरतापूवर्क कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाए। नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब सामग्री को जब्त करने की कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को सागर के बुन्देलखंड मेडिकल चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में जनप्रतिनिधियों, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य शासन अपराध और असामाजिक गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले के साथ-साथ आस-पास और सीमावर्ती क्षेत्रों में गहन जांच अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा जहाँ कहीं भी शंका या संदिग्ध गतिविधि की गुंजाइश हो, वहाँ तत्परता से पड़ताल की जाए और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को कहा कि पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।

फाँसी व आजीवन कारावास देने का कानून है : मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के रहते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय कठोर कानून बनाया गया कि इसमें धारा 49 और बाकी 304 जोड़ते हुए हत्या से लेकर आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा देने का प्रावधान है। इस प्रकार की घटना में लिप्त है, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमने प्रशासन को फ्री हैंड दिया है कि वह उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, जिनके अवैध अतिक्रमण हैं या अलग से किसी ने इस प्रकार से अपना साम्राज्य चलाया है, उस पर भी काम करें।

इरशाद वली सागर पुलिस रेंज के नए आईजी

मुख्यमंत्री ने मामले की न्यायिक जांच कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि आमजन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस मामले में सभी दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही और अनियमितता पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। सभी की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिलीप कुमार ने सागर संभाग के आयुक्त पद की कमान संभाल ली है। इरशाद वली को सागर पुलिस रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) की जिम्मेदारी सौंपी है।

नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह ध्वस्त किया जाए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में नशा विरोधी अभियान को गति देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह ध्वस्त किया जाए। साथ ही, नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को साथ लेकर जनजागरूकता और नशा मुक्ति के प्रभावी कार्यक्रम संचालित किए जाएं।

नशा मुक्ति के लिए सबको मिलकर प्रयास करने की जरूरत : मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पूरे राज्य में निर्देश जारी किए हैं कि नशा मुक्ति अभियान चलाने के लिए धार्मिक संस्थाओं के साथ, सामाजिक संस्थाओं के साथ-साथ अलग-अलग स्तर पर शासन की ओर से भी नशा मुक्ति के अभियान चलाने की आवश्यकता है। हम सबको इससे निपटने के लिए सामाजिक स्तर पर भी प्रतिबद्धता की जरूरत पड़ेगी।

अफवाह फैलाने वालों पर करे सख्त कार्रवाई : मुख्यमंत्री ने शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने की मंशा से सोशल मीडिया या अन्य विभिन्न माध्यमों पर अनावश्यक अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर पैनी नजर रखने और उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

परिजनों से कहा - सरकार आपके साथ

बंडा के अवैध शराब मामले के प्रभावितों को त्वरित राहत देने और उनका ढांढस बंधाने के लिए मुख्यमंत्री सागर स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने अस्पताल के वार्डों में जाकर भर्ती मरीजों का कुशलक्षेम जाना और पीड़ित परिवारों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने परिजन से कहा कि सरकार हर स्थिति में आपके साथ है। मुख्यमंत्रीने प्रत्येक मरीज के पास जाकर उनके स्वास्थ्य की स्थिति देखी। पीड़ितों के परिजनों से पूछा— 'परिवार में कौन-कौन है? चिंता मत करिए, सरकार हर स्थिति में आपके साथ खड़ी है।' निरीक्षण के दौरान सीएम ने बीएमसी के प्रभारी डीन, अधीक्षक और वरिष्ठ चिकित्सकों से पीड़ितों को सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। साथ ही आवश्यक दवाओं, टेस्ट और विशेषज्ञों की तैनाती 24 घंटे सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

रेलवे के सात प्रोजेक्ट को चार लेन में बदलने की मंजूरी

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, रेल नेटवर्क विस्तार को मिली नई रफ्तार

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे से जुड़े सात महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को चार लेन में विकसित करने की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना और ट्रेनों के संचालन को अधिक सुचारू बनाना है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद रेल यातायात में सुधार आने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल के निर्णय के तहत रेलवे के इन प्रोजेक्ट को चार लेन की सुविधा के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इससे रेल पटरियों पर बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी और ट्रेनों के आवागमन में आने वाली देरी को घटाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से रेलवे व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। रेलवे लगातार अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रहा है। इसी दिशा में नई परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है, ताकि बढ़ती यात्री और माल ढुलाई की जरूरतों को पूरा किया जा सके। चार लेन की व्यवस्था से रेल मार्गों की क्षमता में विस्तार होगा और ट्रेनों के संचालन में अधिक लचीलापन आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले को रेलवे विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ट्रेनों की आवाजाही में सुधार के साथ-साथ समय की बचत भी होने की संभावना है। सरकार की ओर से रेलवे क्षेत्र में आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए लगातार योजनाएं लागू की जा रही हैं।

भारत रत्न वैज्ञानिक राव को नोटिस

नईदुनिया ब्यूरो, बेंगलुरुः कर्नाटक में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद भारत रत्न वैज्ञानिक सीएनआर राव को नाम में गड़बड़ी के मामले में नोटिस जारी किया गया है। पुराने रिकॉर्ड में उनका नाम 'प्रोफ सीएनआर राव' दर्ज है, जबकि नए रिकॉर्ड में 'प्रॉफ सीएनआर राव' लिखा गया है। नोटिस में उन्हें मामले के समाधान के लिए मल्लेश्वरम में सुनवाई के लिए उपस्थित होने को कहा गया है। हालांकि, राव के कार्यालय ने कहा कि उन्हें अब तक नोटिस नहीं मिला है। राव को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया।

प्रो. कुमार सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विवि के कुलपति नियुक्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय मंगुभाई पटेल ने पूर्व वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बिमलेन्द्र कुमार को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। राज्यपाल श्री पटेल ने प्रो. कुमार को कार्य भार ग्रहण करने की दिनांक से 4 वर्ष तक अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए कुलपति नियुक्त किया है।

अवैध इमारतों पर चलेगा बुलडोजर, पांच गिरफ्तार

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः दिल्ली के सत्य निकेतन में पीजी इमारत गिरने की घटना के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगर निगम को अवैध पीजी और हॉस्टलों की जांच करने के लिए कहा है।

दिल्ली नगर निगम ने सत्य निकेतन में गिरी पीजी इमारत के आसपास की इमारतों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इन इमारतों में गर्ल्स पीजी संचालित हो रहे थे। यहां रह रहीं छात्राएं पीजी खाली कर दूसरी जगह स्थानांतरित हो रही हैं। मंगलवार तक 24 संपत्तियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, जबकि सात अवैध ढांचों को सील किया गया। सत्य निकेतन में छह सितंबर को पांच मंजिला पीजी इमारत गिरने से सात लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में बुधवार तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में पीजी मालिक, संचालक और श्रमिक ठेकेदार शामिल हैं। पुलिस ने पीजी संचालक सुधांशु को गिरफ्तार किया है। वह हॉस्टल डेज नाम से पीजी चला रहा था। इससे पहले इमारत मालिक हरिराम बंसल, उनकी पत्नी उर्मिला, बेटे महेश और श्रमिक ठेकेदार सनोज को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

सीएम-मंत्रियों की नकली आवाज से अफसर ने करोड़ों रुपये ठगे

नईदुनिया ब्यूरो, गुवाहाटीः असम में राज्य सिविल सेवा के अधिकारी देवेश्वर बोरा पर सरकारी ठेका, नौकरी और शराब की दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है। बोरा धेमाजी में जिला विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री सतर्कता विभाग ने उन्हें मंगलवार को गिरफ्तार किया।

जांच में सामने आया है कि ठगी का सिलसिला वर्ष 2011 से चल रहा था। आरोप है कि बोरा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, मुख्य सचिव और अन्य नेताओं व मंत्रियों की आवाज की नकल कर लोगों को फोन करवाता था। इससे वह लोगों को अपनी ऊंची राजनीतिक पहुंच का भरोसा दिलाता था। सतर्कता विभाग के अनुसार, बोरा ने एक व्यक्ति से दो करोड़ रुपये और दूसरे से 50 लाख रुपये लिए। राजनीतिक नेता रमेन बरठाकुर से भी 50 लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। सरकारी बंगले की मरम्मत के बाद ठेकेदार को भुगतान नहीं करने की शिकायत भी सामने आई है। जांच में बोरा के साथ एक पूरी टीम के काम करने की जानकारी मिली है। विभाग नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रहा है। विभिन्न शिकायतों और प्राथमिकी को जोड़कर बोरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एजेंसी ठगी की कुल रकम और पीड़ितों की संख्या का पता लगा रही है।

10 अक्षरों और अंकों का होगा विशेष कोड

अब आपके घर 'डिजिपिन कोड' से पहुँचेगा पोस्टमैन

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः भारतीय डाक ने देश में स्थानों की डिजिटल पहचान के लिए डिजिपिन यानी डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर की शुरुआत की है। इसके तहत हर स्थान को 10 अक्षरों और अंकों से बना एक विशेष कोड मिलेगा। इससे किसी जगह की पहचान मौजूदा छह अंकों वाले पिन कोड की तुलना में अधिक सटीक तरीके से की जा सकेगी। डिजिपिन को मौजूदा पिन कोड की जगह नहीं लाया गया है। इसका उपयोग पुराने पते और पिन कोड के साथ किया जा सकेगा। इसे आईआईटी हैदराबाद और इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से तैयार किया है। डिजिपिन से ऐसे स्थानों की पहचान आसान होगी, जहां मकान नंबर, गली या सड़क की जानकारी स्पष्ट नहीं होती। गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है। डिजिपिन के माध्यम से किसी भी स्थान की डिजिटल पहचान अधिक सटीक रूप से की जा सकेगी। यह व्यवस्था पते से जुड़ी जानकारी को बेहतर बनाने और स्थान खोजने की प्रक्रिया को आसान करने में मदद करेगी।

सीजेपी से घबराए सीजेआई मजिस्ट्रेट को लगाई फटकार

जंतर-मंतर प्रदर्शन में शामिल छात्र को नोटिस पर मुख्य न्यायाधीश नाराज

नईदुनिया ब्यूरो, नोएडाः कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) से देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) इतने घबराए हुए हैं कि जंतर-मंतर प्रदर्शन में शामिल एक छात्र को जब नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने नोटिस दिया तो, सीजेआई ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट छात्र विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकी रद्द कर चुका है और भविष्य में किसी छात्र के खिलाफ जबरदस्ती की कार्रवाई पर रोक लगा चुका है, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने छात्र को नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे की। उन्होंने कहा कि कोई भी मजिस्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता।

दरअसल, चार सितंबर को नोएडा कमिश्नरेट के तीसरे कार्यकारी मजिस्ट्रेट आरके सिसोदिया ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल छात्र अक्षत त्रिपाठी को नोटिस जारी किया था। नोटिस में छात्र से शांति बनाए रखने के लिए पांच लाख रुपये का व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने को कहा गया था। इसके बाद छात्र ने मंगलवार को वीडियो जारी कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उसे प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर धमकाया जा रहा है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को मामले की जानकारी दी।

विज्ञान *नेवियर-स्टोक्स समस्या हल करने में बड़ी उपलब्धि, 88 घंटे में मिला समाधान...*

ओपनएआई का दावा, 181 साल पुरानी गणित पहेली सुलझाई

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः ओपनएआई ने दावा किया है कि उसकी नई कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक ने गणित की सबसे कठिन समस्याओं में शामिल नेवियर-स्टोक्स समस्या को हल करने में सफलता हासिल की है। कंपनी के अनुसार, एआई प्रणाली ने इस समस्या पर काम करते हुए 88 घंटे में समाधान खोजा। यह समस्या वर्ष 1845 से अनसुलझी थी। अमेरिकी संस्था क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ने वर्ष 2000 में गणित की सात बेहद कठिन और अनसुलझी समस्याओं को चुना था, जिन्हें मिलेनियम प्रॉब्लम्स कहा गया। इनमें से किसी समस्या को सही तरीके से हल करने वाले के लिए 10 लाख डॉलर के पुरस्कार की घोषणा की गई थी।

ओपनएआई के दावे से पहले इन सात समस्याओं में से केवल एक समस्या का समाधान हुआ था। रूसी गणितज्ञ ग्रिगोरी पेरेलमैन ने वर्ष 2003 में प्वांकारे कन्जेक्चर को हल किया था। यदि ओपनएआई का दावा सही साबित होता है तो इन समस्याओं में से दूसरी समस्या का समाधान माना जाएगा। नेवियर-स्टोक्स समस्या तरल पदार्थों के बहाव से जुड़ी है। इसके माध्यम से यह समझने की कोशिश की जाती है कि पानी और हवा किस दिशा में और कितनी गति से बहते हैं। वैज्ञानिकों के सामने सवाल था कि क्या इन समीकरणों से हर स्थिति में बहाव का सही अनुमान लगाया जा सकता है या कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जहां ये समीकरण काम करना बंद कर दें।

ओपनएआई के अनुसार, उसके नए आंतरिक एआई मॉडल ने इस समस्या पर करीब 10 हजार एआई एजेंट्स की मदद से काम किया। इस प्रक्रिया में लगभग 30 लाख संदेशों का आदान-प्रदान हुआ और करीब 130 अरब आउटपुट टोकन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि कंपनी ने स्पष्ट किया है कि एआई से मिले समाधान ने समस्या से जुड़ी चार में से दो अहम बातों को ही साबित किया है। इसलिए पूरी समस्या का समाधान अभी पूरा नहीं माना जा सकता। ओपनएआई ने 10 लाख डॉलर के पुरस्कार का दावा भी नहीं किया है।

इस दावे को लेकर विवाद भी सामने आया है। गणितज्ञ ट्रिस्टन बकमास्टर और एंथ्रोपिक से जुड़े गणितज्ञ लेवेंट अल्पोगे भी इसी समस्या पर काम कर रहे थे। बकमास्टर ने दावा किया कि उनकी शोध से जुड़ी जानकारी ओपनएआई तक पहुंच गई थी, हालांकि ओपनएआई ने कहा कि उसने उनका काम सार्वजनिक होने से पहले नहीं देखा था। गणितज्ञों का मानना है कि एआई की तेज क्षमता से शोध में मदद मिल सकती है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों को चिंता है कि यदि मशीनें समाधान देने लगेंगी तो इंसानों की समस्या समझने और हल करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।